

प्रेषक,

पी०सी० शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 29 अप्रैल, 2011

विषय:- ग्राम रुड़की, परगना व तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार में ए०डी०बी० वित्त पोषित, यू०यू०एस०डी०आई० में प्रस्तावित सीवरेज कार्य हेतु 3.00 है० भूमि शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड को निशुल्क हस्तान्तरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या-982/भूमि व्यवस्था-11, दिनांक 4.2.2011 के सन्दर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, ग्राम रुड़की, परगना व तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार में ए०डी०बी० वित्त पोषित, यू०यू०एस०डी०आई० में प्रस्तावित सीवरेज कार्य हेतु 3.00 है० भूमि शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड को, वित्त अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-260/वित्त अनुभाग-3/2002 दिनांक-15.02.02 एवं शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा दी गई सहमति/अनापत्ति के दृष्टिगत, जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा संस्तुत किये गये खसरा संख्या 254 म० के अनुसार निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन, निःशुल्क हस्तान्तरण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- 1- भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
- 2- जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी है।
- 3- हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 4- यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।
- 5- जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
- 6- जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

- 7- प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु, तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जनपद स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति अनिवार्य रूप से शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

1
(पी०सी० शर्मा)
प्रमुख सचिव।

पृ०प०संख्या-५५२/समदिनांकित/2011

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3- निदेशक, एन०आई०सी० सचिवालय। ✓
- 4- प्रभारी मीडिया केन्द्र सचिवालय।
- 5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

माफ़ी
(मयावती ठकुरियाल)
उप सचिव।